आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 05.08.2026 **समय : 1905**

1. लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया। अब बैंक के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को मिलेगा वैध साक्ष्य का दर्जा।
2. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा डिजिटल दुनिया में बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बना रही मजबूत कानूनी और जागरूकता तंत्र।
3. समग्र शिक्षा के तहत हटबे के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया।
4. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने जेम्स ऑफ इंडिया चौलेंज 2026 में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागों से किया व्यापक प्रचार का आग्रह।

<><><><><><><><>

लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। यह कानून बैंकिंग व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

<><><><><><><><>

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6 दशमलव 7 प्रतिशत कर दिया है। आर बी आई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5 दशमलव 25 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अप्रैल–जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान पांच दशमलव एक प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, हाल में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।

<><><><><><><><>

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है जिनमें हानिकारक सामग्री देखना, डिजिटल उपकरणों जैसे फोन, कंप्यूटर या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जानबूझकर डराने, अपमानित करने, परेशान करने या नीचा दिखाने का ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन शोषण और डिजिटल लत शामिल हैं। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है जिनमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू किया गया है जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। डीपीडीपी अधिनियम बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन तैयार करने और आम जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य जागरूकता के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पर परियोजना शुरू कर रहा है।

<><><><><><><><>

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आज सी आर सी, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हटबे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों केलिए पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में चिकित्सकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छब्बीस विद्यार्थियों की जाँच की, जिनमें से चार विद्यार्थियों को आगे की जांच के लिए चिह्नित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों को बच्चों की प्रारंभिक पहचान और समग्र शिक्षा के तहत उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गई। पात्र बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री और ब्रेल किट भी वितरित की गई।

<><><><><><><><>

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के माय वेब्स मंच के माध्यम से ''जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज–2026'' शुरू किया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने संबंधित विभागों से इस राष्ट्रीय पहल का प्रचार–प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न जिलों के उभरते डिजिटल सामग्री निर्माताओं को अपनी स्थानीय संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक परंपराओं और प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देना है। प्रतिभागी लघु वीडियो, रील, वृत्तचित्र, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल सामग्री तैयार कर माय वेब्स मंच पर अपलोड कर सकते हैं।

<><><><><><><>

उद्योग विभाग ने द्वीप समूह के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से एम एस एम ई सतत शून्य दोष – शून्य पर्यावरणीय प्रभाव प्रमाणन योजना यानी जेड ई डी प्रमाणन योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और पर्यावरण–अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। जेड ई डी प्रमाणन ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड स्तर पर उपलब्ध है। योजना के तहत पात्र उद्यमों को प्रमाणन के लिए सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए इच्छुक उद्यमी मिडिल प्वाइंट स्थित जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

अंडमान एवं निकोबार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक परीक्षा सात अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा स्थल, तिथि और रिपोर्टिंग समय पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तर फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का आज भातू बस्ती स्कूल मैदान में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञान शील दुबे ने किया।

<><><><><><><>

जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम परामर्श प्रक्रिया दस अगस्त को आयोजित की जाएगी। महाविद्यालय परिसर में होने वाली इस परामर्श प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सुबह साढ़े आठ बजे तक संबंधित विभाग में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाणपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

<><><><><><><>

भारतीय सेना की पूर्व इक्हत्तर इंजीनियर रेजीमेंट की ओर से चिन्थे लॉन्ग रेंज क्षेत्र में फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास आठ अगस्त को सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान आम नागरिकों को अभ्यास क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

<><><><><><><>